## [Shri R. P. Ulaganambi.]

State alone or the Bill is brought forward as a national issue for the country as a whole, I would like to say one thing. The Archaeological Department does not take any care to maintain and preserve the national monuments. Also, the purpose of my bringing forward this Bill is this. This is just to instal, erect, build or construct a suitable momorial in, or near, or in the vicinity of, a protected monument or a protected area to perpetuate the memory of the person, who was either the founder. or the builder or the originator of the idea for the installation, erection, building or construction of such a monument. I am not speaking as an individual belonging to D.M.K. Partv. Irrespective of the fact whether one belongs to D.M.K. A.D.M.K. or any other party, the purpose of this Bill is only for amending Section 20A to the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. My amendment to 20A(2) is as follows :--

"(2) The Memorial so installed, erected, constructed or built shall be such as not to have the effect of destroying, removing, injuring, defacing, imperilling or misusing the protected monument."

That is the guarantee that is given in this Bill. It is not that any individual party or Member with vast majority of votes comes forward with this Bill for installing a statue. This reflects the aspiration of the people of the locality who want to instal or erect the statue. That should be considered. That is the spirit behind this Bill. It is not my intention to bring in any party issue or any individual's issue.

MR. CHAIRMAN: Those things are clearly mentioned in the Bill. Tell us whether you are willing to withdraw this Bill or not.

SHRI R. P. ULAGANAMBI: It is not unconstitutional as one hon. Member said. I only want an amendment to Section 20. If the Minister accepts this, then only he can bring forward an amendment to the Constitution. It is not unconstitutional. It is within the purview of the Constitution.

Prof. Mukerjee raised this issue—he is not here—and he also appreciated the maintenance of the Madurai temple. Also he appreciated the panoramic view of the Cape Comerin—Kanyakumari. Madurai temple is looked after by the State Government. That is why it is properly looked after a great struggle we got the limited permission to garden the open space around Vellore Fort. If any State Government comes forward and pass a resolution by majority to take over any temple or erect any statue then only the Bill seeks for your consideration.

MR. CHAIRMAN: Do you want to withdraw the Bill or not?

act SHRI R. P. ULAGANAMBI: I seek or leave of the House to withdraw the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to Shri R. P. Ulaganambi to withdraw the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 1972."

The motion was adopted.

SHRI R. P. ULAGANAMBI: I withdraw the Bill.

## MOTHER'S LINEAGE BILL

17.50 hrs.

श्री मधु लिमये (बांका) I beg to move :

"That the Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother be taken into consideration."

सभापित महोदय, भ्राज सारा विषव सप्त कान्तियों की चपेट में है। यह सात कान्तियां कम श्रीधक माला में दुनिया के विभिन्न देशों में चल रही हैं, भौर हमारा ऐसा देश जिसने इनमें से कुछ कान्तियों में श्रगुवाई की थी इस देश को तो इनके सभी पहलुकों पर बड़ी गम्भीरता से गौर करना चाहिये। इन सप्त कान्तियों में एक कान्ति है श्राधिक समानता की, गरीबी भौर ग्रमीरी के बीच में जो खाई है उसको मिटाने वाली।

भीर दसरी कान्ति है सामाजिक समानता की, जन्म पर ग्राधारित जाति की कल्पना को समाप्त करने वाली । तीसरी कान्ति है काले-गोरे की ग्रसमानता को मिटाने वाली वंशवार-विरोधी कान्ति । चौथी कान्ति है उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की कान्ति । दनिया के अधिकतर हिस्सों में तो यह क्रान्ति सम्पन्न हुई है, लेकिन ग्रफीका में, खास करके पूर्तगाली साम्राज्य के नीचे प्राज भ्रफीका के कई देश हैं जिनको राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह कान्ति भी आज अधरी है। पांचवीं कान्ति है पंजीवाद भौर ग्रसमानता-विरोधी कान्ति । छठी कान्ति है एक तिहाई विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों की दुनिया, एक तिहाई दुनिया, ग्रौर दूसरी ग्रोर ग्रविकसित राष्ट्रों की दो तिहाई दुनिया इनके बीच में जो मतभद है। विगत 27 सालों में कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको खत्म करना भी प्रावश्यक है। ग्रीर सातवीं कान्ति है नर-नारी समानता की कान्ति । भीर इस विधेयक का सम्बन्ध इस सातवीं कान्ति से है। यह सातवीं कान्ति ही इसका ग्राधार है।

सभापति महोदय, मेरा जो विधेयक है उसका मकसद तो सीमित है। मगर इसके द्वारा मैं उन सारे सवालों को उठाना चाहता हं जिनका सम्बन्ध उदारता भीर समानता से है। हमारे संविधान में सभी लोगों को कानृन के सामने समानता प्रदान की गई है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कान्न की इस मान्यता को भाज कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। कान्न ने कहा है कि सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण मिले । लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह का समान संरक्षण भाज नहीं मिल रहा है। समाज में कुछ लड़कों को, कुछ बच्चों को मनौरस भौर मबैध माना जाता है, उनके कदम-कदम पर भ्रपमानित किया जाता है। नतीजा यह होता है कि यह मासूम बच्चे, यह फल बचपन में ही मर्झा जाते हैं। तो क्या इस सदन का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जिन बच्चों का कोई भपराध नहीं है उनके साथ इस तरह का व्यवहार कम से कम कानुन भौर संविधान के भाधार पर न किया जाय, भीर इस तरह का एक भ्रान्दोलन हम लोग चलायें जिससे समाज की जो कल्पना, समाज के जो धनुदार विचार हैं, परम्परागत विचार हैं उनमें कोई परिवर्तन घाये ?

सभापित महोदय, म्राज का समाज, इसके बारे में दो रायें नहीं हैं कि, सम्पत्त-प्रभिमुख भीर पुरुष-प्रधान है भीर बहुत सारे जो माधार हैं कानून के भीर मान्यताओं के, इसके पीछे यही दिकयानूसी दृष्टिकोण है । भीर नतीजा यह होता है कि सम्पत्त-प्रभिमुख भीर पुरुष प्रधान समाज भविवाहित माताओं को पतिता का दर्जा देता है भीर उनकी सन्तित के साथ दुर्ब्यवहार करता है । इसलिये इस विधेयक के हारा में इस बात का प्रारम्भ करना चाहता हूं । इससे सारी समस्यायें तो समाप्त नहीं होतीं, लेकिन इस विधेयक के द्वारा एक नई उदारवादी परम्परा कायम करने की मैं कोशिण कर रहा हं ।

सभापति महोदय, हमारे प्राचीन इतिहास की भ्रोर देखा जाय तो हमेशा ऐसी माताभ्रों की तरफ भ्रोर बच्चों की तरफ देखने का दृष्टिकोण हमेशा भ्रनुदार नहीं रहा है।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may please continue his speech next time.

Now we take up Half-an-Hour Discussion.

18.00 hrs.

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SUPPLY OF MACHINERY TO HEAVY ENGINEERING CORPORATION, RANCHI

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): I rise to raise a discussion on points arising out of the reply given to my unstarred question No. 2231 on 7th March, 1974 in connection with the Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

The reply to my question was given by the Deputy Minister of Heavy Industry; regarding the non-supply of complete machinery, plant and machine-tools for the heavy Engineering Corporation, Ranchi,